Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

नवंबर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- नमामि गंगे'और पतंजलि के बीच अनुबंध 3
- उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सोविनियर बनाने के निर्देश 3
- आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन 4
- निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड 4
- स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देशभर में मिला 35वाँ स्थान 5
- पाँच विभूतियों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 6
- प्रदेश में खनन की 'वन स्टेट वन रॉयल्टी' नीति होगी लागू 6
- कुमाऊँ की दो नर्सों को मिला 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड' 7
- चार ज़िलों के 12 निकायों में गरीबों के लिये बनेंगे 2187 आशियाने 7
- उत्तराखंड को फिर मिली राष्ट्रीय शीत खेलों की मेज़बानी 8
- उत्तराखंड का 23वाँ स्थापना दिवस 8
- ईको पार्क से मिलेगी डांडाचली को नई पहचान 9
- मुख्यमंत्री ने 'अपणि सरकार' मोबाइल ऐप किया लॉन्च 9
- उत्तराखंड में चालान सहित परिवहन विभाग की छह सेवाएँ हुईं ऑनलाइन 10
- दिल्ली की तर्ज पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास बनेगी उत्तराखंड की पहली एयरोसिटी 11
- प्रदेश में खुलेंगे 206 पीएम श्री स्कूल 11
- लक्ष्य सेन को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 12
- 70वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले (गौचर मेला) का शुभारंभ 13
- प्रसिद्ध जौलजीबी मेला का हुआ शुभारंभ 13
- प्राकृतिक खेती के लिये प्रति हेक्टेयर पाँच हज़ार रुपए देगी केंद्र सरकार 14
- उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप होगा अपग्रेड 14
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 पर कैबिनेट की मुहर 15
- बर्ड वॉचिंग ट्रैल के रूप में विकसित होगा एबट माउंट क्षेत्र 15
- मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना 15
- उत्तराखंड में बनाई जाएगी पोल्ट्री वैली 16
- उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 का ड्राफ्ट जारी 16
- सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव-2022 का शुभारंभ 17
- देहरादून नगर निगम ने लॉन्च किया 'बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप' 18
- सहस्त्रधारा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीड्रोम 18
- उत्तराखंड और अमेरिकी कंपनी के बीच हुआ दो साल का करार 19
- उत्तराखंड में ड्रोन ट्रैफिक सँभालने के लिये बनेंगे कॉरिडोर 19
- गौचर व चिन्यालीसौड़ के लिये जल्द हवाई सेवा, पिथौरागढ़ से शुरू होंगी फिक्स्ड विंग एयरक्रॉफ्ट सेवाएँ 20

नोट :

उत्तराखंड

नमामि गंगे'और पतंजलि के बीच अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

31 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में पतंजलि आर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से आयोजित गंगा बेसिन क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम के अवसर पर प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिये 'नमामि गंगे' और पतंजलि के बीच अनुबंध हुआ।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में योगगुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डीजी नमामि गंगे अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने नेचुरल फार्मिंग इन गंगा बेसिन रीजन (पर्सपेक्टिव एंड साल्यूशन) किताब का विमोचन भी किया।
- इसके अलावा गंगा रन में प्रतिभागी प्रथम 20 बच्चों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पतंजलि अनुसंधान केंद्र और नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा इन दोनों के बीच में जो एमओयू का करार हुआ है, यह ऐतिहासिक अवसर है।
- विदित है कि योगगुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने संसार में योग और आयुर्वेद को प्रतिष्ठित किया है और आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पतंजलि से अछूता रहा हो।
- इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि संपूर्ण संसार में 60 लाख के आस-पास वनस्पति पायी जाती है और भारत में लगभग 20 हज़ार प्रकार की वनस्पति पायी जाती है और गंगा के किनारों पर हज़ारों प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
- उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती करने से पहले यह सोचने की आवश्यकता है कि किस चीज की खेती करें और किस खेती को कहाँ करने से किसानों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है।

उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सोविनियर बनाने के निर्देश

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने एमएसएमई की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सोविनियर तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- डॉ.एसएस संधू ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के लिये सोविनियर तैयार होने से राज्य में युवाओं एवं महिलाओं हेतु स्वरोज़गार की राह खुलेगी।
- उन्होंने बताया कि सोविनियर के लिये डिज़ाइन, गुणवत्ता, उत्पादन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाना चाहिये तथा सोविनियर के साइज और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि श्रद्धालुओं को इन्हें ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
- मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करने तथा राज्य स्तर व ज़िला स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। किसी भी प्रकार की योजना को लाने के लिये निवेशकों से सुझाव लेने और उनके सामने आ रहीं समस्याओं के निराकरण पर फोकस करते हुए निवेशकों को अधिक-से-अधिक सपोर्ट करना चाहिये।

नोट :

- उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में फील्ड स्तर पर फीडबैक ज़रूर लिया जाए, ताकि उद्यमियों की ओर से योजनाओं का अधिक-से-अधिक लाभ लिया जा सके।
- उन्होंने एक ज़िला, दो उत्पाद को बढ़ावा देने, इन्हें ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने और विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिये, ताकि सिंगल विंडो से निवेशकों को लाभ मिले।

आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। समझौते के मुताबिक, दोनों संस्थाओं के बीच जल संसाधन संबंधी आँकड़े साझा हो सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- आपदा प्रबंधन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस समझौते के तहत राज्य की बड़ी नदियों में जल स्तर मापने के लिये सेंसर लगाए जाएंगे। ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर की मदद से एक ही जगह पर रियल टाइम डाटा की जानकारी मिलती रहेगी तथा रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये विकसित तंत्र राज्य सचिवालय में बने आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल से सीधे जुड़ेगा।
- इससे नदियों और बांधों में लगाए गए सभी सेंसर से सारा डाटा आपदा कंट्रोल रूम को प्राप्त होता रहेगा। आपदा कंट्रोल रूम को प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर बाढ़ के खतरे की स्थिति के दौरान रियल टाइम में चेतावनी जारी हो सकेगी।
- पहले चरण में सभी नदियों से मैनुअल सेंसर हटाकर उनकी जगह ऑटोमेटिक सेंसर लगाए जाएंगे। ये सेंसर केंद्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत लगाए जाएंगे। राज्य के सभी बांधों की अपस्ट्रीम में ऑटोमेटिक सेंसर लगेंगे और डाउन स्ट्रीम में ऑटोमेटिक सायरन स्थापित होंगे।
- उन्होंने बताया कि नदियों और बांधों के जल स्तर को मापने के लिये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आपदा प्रबंधन में बहुत मददगार होगा तथा एक ही जगह डाटा प्राप्त होने से चेतावनी तंत्र प्रभावी हो सकेगा। यह तंत्र दो महीने में तैयार कर लिया जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य में आईआरआई, रुड़की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत नदियों में ऐसा तंत्र विकसित कर रहा है, जिससे उत्तराखंड की बड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ेगा तो आपदा प्रबंधन विभाग को इसका तुरंत अलर्ट मिल जाएगा।
- बांधों की डाउन स्ट्रीम में भी ऑटोमेटिक सेंसर लगेंगे तथा बड़ी नदियों और बांधों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित हो सकेगा।

निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण कर उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान पाया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड टीबी मरीज़ों की औसत संख्या के आधार पर देश भर में सर्वाधिक निक्षय मित्र पंजीकरण करने वाला राज्य बना है। निक्षय मित्र के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, गैर-सरकारी संगठन, कॉरपोरेट संस्थानों समेत कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है।
- निक्षय मित्र के रूप में प्रत्येक व्यक्ति एक या एक-से-अधिक टीबी रोगियों को कम-से-कम एक वर्ष तक गोद लेकर उपचार में सहयोग करेगा तथा निक्षय मित्र केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए फूड बास्केट प्रत्येक माह रोगी को उपलब्ध कराएगा, जिसकी अनुमानित लागत एक हज़ार रुपए है।

नोट :

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के तीन जनपदों- टिहरी गढ़वाल, चमोली और चंपावत में शत-प्रतिशत निक्षय मित्रों को रोगी की देखभाल व उपचार के लिये लिंकेज किया गया है, जबकि पाँच ज़िलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में 95 फीसदी से अधिक निक्षय मित्रों का लिंकेज किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अभी तक राज्य में 5852 निक्षय मित्र बनाए गए हैं। इनमें से 91 प्रतिशत निक्षय मित्रों का टीबी मरीज़ों के साथ लिंकेज कर दिया गया है।

स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देशभर में मिला 35वाँ स्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई। इस इंडेक्स में देशभर में उत्तराखंड को 35वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में उत्तराखंड को 1000 अंकों में से 719 अंक प्राप्त हुए हैं।
- शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब 1000 अंकों के स्कोर में 928 अंक पाकर पहले, 927 अंकों के साथ चंडीगढ़ दूसरे और 903 अंकों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है।
- ज़िला और राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करती यह रिपोर्ट बताती है कि बीते चार वर्षों में उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा का स्तर कभी भी ऊपर नहीं उठ पाया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड का स्कोर इस इंडेक्स में 752 अंक था जो अब वर्ष 2020-21 में 33 अंक लुढ़ककर 719 पर आ पहुँचा है। इससे पूर्व वर्ष 2017-18 में अंकों का यह स्कोर 704 और वर्ष 2018-19 में 712 था।
- परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) एक ऐसा सूचकांक है, जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों को उत्प्रेरित करने के लिये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को एक समान पैमाने पर मापता है।
- पीजीआई का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर नज़र रखने के साथ उन्हें उनके बेहतर प्रदर्शन करने और शिक्षा प्रणाली को हर स्तर पर मज़बूत बनाने के लिये प्रेरित करना है।
- इस रिपोर्ट में 70 मानकों में कुल 1000 अंक शामिल हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में बाँटा गया है। इन श्रेणियों को आगे पाँच डोमेन में विभाजित किया गया है। इनमें डोमेन-एक में लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी के लिये नौ मानकों में 180 अंक, डोमेन-2 में एक्सस के आठ मानकों में 80 अंक, डोमेन-3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिये 11 मानकों में 150 अंक, डोमेन-4 में इक्विटी के लिये 16 मानकों में 230 अंक, कुल 640 अंक रखे गए हैं।
- इसके अलावा दूसरी श्रेणी सुशासन और प्रबंधन में 26 मानकों में 360 अंकों को शामिल किया गया है। इसी श्रेणी में उत्तराखंड को सबसे कम अंक मिले हैं।
- पीजीआई रिपोर्ट में उत्तराखंड के खराब प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपलब्धता के चलते पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाई हैं।
- डॉ. धनसिंह रावत ने कहा कि सुशासन और प्रबंधन (गर्वनेंस एंड मैनेजमेंट) के मामले में इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। इसकी वजह पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सी जगह इंटरनेट की पहुँच का न होना है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय सारा डाटा यू-डायस पोर्टल से लेता है। इस पोर्टल पर सारी डिटेल स्कूल भरते हैं, जिसमें बच्चों की परफॉरमेंस से लेकर स्कूल में मौजूद बिजली-पानी और अन्य सुविधाओं की जानकारी देनी होती है।
- इंटरनेट की कमी के चलते बहुत से स्कूल इन तमाम जानकारियों को नहीं भर पाए हैं। शिक्षा विभाग विद्या समीक्षा केंद्र ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसमें रियल टाइम डाटा भरा जाएगा, अगले छह माह में सारी जानकारियां इसमें भर दी जाएंगी।

नोट :

पाँच विभूतियों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2022 को प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन, उत्तराखंड विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। इसमें पाँच अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिये पाँच विभूतियों को पुरस्कार हेतु चुना गया है। इनमें से तीन को मरणोपरांत पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को यह पुरस्कार दिया जाएगा।
- पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्व. जनरल बिपिन रावत, कवि, लेखक और गीतकार रहे स्व.गिरीश चंद्र तिवारी और साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में स्व. वीरेन डंगवाल को मरणोपरांत इस पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है।
- प्रभारी सचिव के मुताबिक, उत्तराखंड गौरव सम्मान दिये जाने की तिथि, स्थान और समय बाद में अलग से जारी किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिये पिछले साल पर्यावरण के क्षेत्र में डॉ.अनिल जोशी, साहसिक खेल के लिये बछेंद्री पाल, संस्कृति के लिये लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बांड के नाम की घोषणा हुई थी। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को मरणोपरांत इस पुरस्कार के लिये चयनित किया गया था, लेकिन पिछले साल कार्यक्रम आयोजित न होने के चलते इन विभूतियों को भी इस साल सम्मानित किया जाएगा।

प्रदेश में खनन की 'वन स्टेट वन रॉयल्टी' नीति होगी लागू

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुंधाशु ने बताया कि प्रदेश की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक, खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने के लिये प्रदेश में 'वन स्टेट, वन रॉयल्टी 'नीति लागू की जाएगी। वन विकास निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर सौंप दिया है। इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

प्रमुख बिंदु

- खनन की रॉयल्टी की दरें एक समान लागू होने से जहाँ अवैध खनन के मामलों में कमी आएगी, वहीं निर्माण सामग्री सस्ती होने से लोगों को घर इत्यादि बनाने में राहत मिलेगी।
- प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्रों में उपखनिज का चुगान (खनन) वन विभाग की ओर से वन विकास निगम को सौंपा गया है तथा इसके अलावा राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन होता है। वहीं, शासन-प्रशासन की अनुमति के बाद निजी पट्टों पर भी खनन किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तीनों तरह के खनन में रॉयल्टी की दरें भिन्न-भिन्न हैं। वन विकास निगम की ओर से आरक्षित वन क्षेत्रों की विभिन्न नदियों में आरबीएम की दरें 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल तय हैं। जबकि राजस्व और निजी खनन पट्टों में यह दरें 15 से 18 रुपए तय हैं।
- ज्ञातव्य है कि प्रदेश में निकलने वाले 65 से 70 प्रतिशत उप खनिज का चुगान आरक्षित वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों से किया जाता है तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित नदियों में खनन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है।
- गाइडलाइन के अनुसार, रॉयल्टी की दरों के साथ सीमांकन एवं सुरक्षा क्षतिपूर्ति पौधरोपण, स्टांप शुल्क, वन्य जीव शमन, श्रमिक कल्याण कोष, धर्मकांटा, कंप्यूटरीकृत तौलाई, सीसीटीवी कैमरा, परिचालन व्यय जैसी तमाम औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं,जिससे वन विकास निगम की रॉयल्टी दरें राजस्व और निजी खनन पट्टों से अधिक हैं तथा अब इन व्ययों के खर्च को कम करने पर मंथन किया जा रहा है, ताकि खनन रॉयल्टी में एकरूपता लाई जा सके।

नोट :

- वन विकास निगम की ओर से दिये गए सुझाव-
  - पूरे राज्य में सभी स्थलों से निकलने वाले खनिजों की मूल रॉयल्टी को प्रति क्विंटल सात रुपए तक किया जा सकता है।
  - ज़िला खनिज न्यास में अंशदान रॉयल्टी को 15 प्रतिशत किया जा सकता है।
  - क्षतिपूरक पौधरोपण में अंशदान रॉयल्टी को 10 प्रतिशत किया जा सकता है।
  - सीमांकन एवं सुरक्षा में वन विभाग का अंशदान 25 रुपए प्रति क्विंटल किया जा सकता है।
  - वन विकास निगम परिचालन व्यय में 25 रुपए प्रति क्विंटल कम करने पर सहमत है।
  - वन विभाग की ओर से रोड फीस 25 प्रतिशत कम करने पर विचार किया जा सकता है।
- प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि उप खनिजों की विक्रय दरें राजस्व की मदें, वन विभाग की मदें, वन विकास निगम की मदें, जीएसटी और आयकर को जोड़कर निर्धारित की जाती हैं। वन अधिनियम की शर्तों को पूरा करने के साथ इस तरह से वन विकास निगम की दरें बढ़ जाती हैं। इन दरों को कैसे कम कर सकते हैं, इसके तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।
- खनन सचिव पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि खनन की रॉयल्टी में एकरूपता लाने के लिये शासन स्तर पर वन विभाग के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिनमें वन विभाग से वन विकास निगम की दरों में संशोधन पर चर्चा की जा रही है। रॉयल्टी में एकरूपता आने से आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और राजस्व में भी वृद्धि होने का अनुमान है।

कुमाऊँ की दो नर्सों को मिला 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड'

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के कुमाऊँ की दो नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में तैनात शशिकला पांडे को यह सम्मान उनकी ओर से मरीज़ों के प्रति समर्पण और नि:स्वार्थ सेवा के लिये दिया गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड पाने वाली शशिकला पांडे बीडी पांडे अस्पताल की मेट्रन हैं।
- वहीं, गंगा जोशी खटीमा के उप ज़िला चिकित्सालय में एएनएम के पद पर तैनात हैं। गंगा जोशी को जागरूकता प्रोग्राम, कोविड-19 में विशेष योगदान, आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई ट्रेनिंग में प्रतिभाग करने पर यह पुरस्कार दिया गया है।
- पिछले दिनों नैनीताल पहुँचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने मेट्रन के परिवार की स्थिति, कार्यों व लगन से प्रभावित होकर उनको 10001 रुपए का इनाम दिया था। 15 जून को राज्यपाल ने बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण किया था। उस दौरान शशिकला पांडे ने राज्यपाल को अस्पताल का निरीक्षण कराया था।
- विदित है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिये मान्यता के रूप में की गई थी।

चार ज़िलों के 12 निकायों में गरीबों के लिये बनेंगे 2187 आशियाने

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2022 को निदेशक, शहरी विकास नवीन पांडेय की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की तकनीकी समिति की बैठक में उत्तराखंड में चार ज़िलों के 12 निकायों में गरीबों के लिये 2187 आशियाने बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बैठक में विभिन्न ज़िलों के अलग-अलग निकायों में गरीबों के आवास बनाने के प्रस्ताव रखे गए। इसमें देहरादून के एक, हरिद्वार के तीन, ऊधमसिंह नगर के पाँच और पिथौरागढ़ के तीन निकायों के 2187 आवासों पर मुहर लग गई।
- बैठक के बाद शहरी विकास निदेशक नवीन पांडेय ने बताया कि बैठक में 12 निकायों की डीपीआर पर मुहर लग गई है। अब प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है।

उत्तराखंड को फिर मिली राष्ट्रीय शीत खेलों की मेज़बानी

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निकट बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा भवन का शिलान्यास करते हुए बताया कि एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है, जिनका राज्य के चमोली के औली में आगामी दो से पाँच फरवरी तक आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन के अलावा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ द्वारा 'हिमालयन ट्रॉफी' का आयोजन भी किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2023 में कुल चार इवेंट होंगे, जिनमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हिमालयन ट्रॉफी 2023 के तहत 7-8 फरवरी को पुरुषों व महिलाओं के लिये एफआईएस स्वीकृत जायंट स्लैलम रेस भी होगी।
- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटन विभाग ने इन खेलों के आयोजनों के लिये पूरी तैयारी कर ली है तथा औली के लिये मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंज़ूरी हेतु भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ साढ़े तीन किमी. रेसिंग ढलान का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे औली स्कीइंग पेशेवरों के लिये शानदार स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकेगा।
- गौरतलब है कि औली में जीएमवीएन द्वारा संचालित पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान भी हैं, जहाँ विशेषज्ञ स्कीइंग में प्रतिभाओं को तैयार करते हैं।
- खेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिये निर्माण संबंधी कार्य करीब 70 फीसदी तक पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य भी छह माह में पूरे कर लिये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर 'सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना' लागू की थी, जिसके तहत वर्तमान में पूरे प्रदेश में करीब पाँच हज़ार खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सामान्य के समान धनराशि और सुविधा मुहैया कराने का काम किया है।

उत्तराखंड का 23वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड का 23वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को 166 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
- उल्लेखनीय है कि एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड 9 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। इससे पूर्व यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक भाग था। अलग राज्य उत्तराखंड की मांग 25 अगस्त, 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के पारित होने के साथ पूर्ण हुई। गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया।

नोट :

- उत्तरांचल 21 दिसंबर, 2006 को उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 के पारित होने पर परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर, 2006 के अनुसार 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी हुआ।
- इसकी सीमा में पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर पूर्व में हैं, जो नेपाल तथा चीन से मिलती हैं। राज्य में 13 ज़िले, यथा- देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चंपावत तथा पिथौरागढ़ हैं।

ईको पार्क से मिलेगी डांडाचली को नई पहचान

चर्चा में क्यों ?

10 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के नई टिहरी ज़िला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि नई टिहरी से मात्र 15 किमी. की दूरी पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल डांडाचली को पर्यटन विभाग द्वारा ईको पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। मंज़ूरी मिलने के बाद डांडाचली देश-विदेश के पर्यटकों को एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल की अनुभूति कराएगा।

प्रमुख बिंदु

- अतुल भंडारी ने बताया कि डांडाचली क्षेत्र पाँच वर्ग किमी. में देवदार व बांज के घने जंगलों से घिरा हुआ है। वाइल्ड लाइफ से भरपूर इस क्षेत्र में गुलदार, भालू, सेही, घुरल जैसे वन्यजीव बहुतायत में हैं। इसके जंगल में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की भी भरमार है। डांडाचली का मौसम जून की गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराता है, जबकि दिसंबर व जनवरी में यहाँ चार से पाँच फीट तक बर्फ जम जाती है।
- उन्होंने बताया कि यहाँ देवदार के जंगल में नेचर ट्रैक बनाए जाएंगे। मचान, व्यू पॉइंट और साहसिक खेलों की सुविधा भी पर्यटकों को मिलेगी। इसके अलावा बर्मा ब्रिज, वुडन व ग्लास हाउस रेस्तरां और माउंटेन बाइक ट्रैक भी यहाँ पर बनाए जाएंगे।
- हालाँकि, डांडाचली में ठहरने के लिये होटल आदि की व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों को शाम ढलने से पूर्व ही चंबा या नई टिहरी वापस लौटना पड़ता है। इसके बावजूद पर्यटकों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। नए साल का जश्न मनाने के लिये हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक डांडाचली पहुँचते हैं, लेकिन डांडाचली के पर्यटन मानचित्र पर न होने के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता।
- डांडाचली में ईको पार्क बनने पर स्थानीय युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा तथा पर्यटकों की आमद बढ़ने से यहाँ दुकान व होम स्टे तो खुलेंगे ही, रोज़गार के अन्य साधन भी विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री ने 'अपणि सरकार' मोबाइल ऐप किया लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

11 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा विकसित 'अपणि सरकार पोर्टल'का मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- 'अपणि सरकार पोर्टल'के लॉन्च होने के बाद यह ऐप अब प्लेस्टोर पर भी उपलब्ध हो गया है। इस मोबाइल ऐप पर राज्य की 254 सेवाएँ और अन्य 173 सेवाएँ वेब लिंक के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस ऐप पर लॉगिन करके आप सेवाओं का लाभ घर-बैठे ले सकते हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की सुविधा भी अब मोबाइल ऐप से मिल सकेगी।
- इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग की चार, लघु सिंचाई विभाग की 15, गृह विभाग की दस, निबंधन विभाग की पाँच, राजस्व विभाग की 18, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दो, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की तीन, शहरी विकास निदेशालय की आठ, पंचायती राज विभाग की 12, समाज कल्याण विभाग की नौ, मत्स्य विभाग की सात, पेयजल विभाग की नौ तथा ऊर्जा विभाग की 23 सेवाएँ सीधे मिलेंगी।

नोट :

- इसी प्रकार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की एक, तकनीकी शिक्षा विभाग की 14, विद्यालयी शिक्षा विभाग की 20, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग की 12, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तीन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 22, आयुर्वेदिक एवं यूनानी की 13, ग्राम्य विकास विभाग की दो, कृषि विभाग की पाँच, कृषि एवं कृषि विपणन विभाग की 19, लोक निर्माण विभाग की दो और विधिक माप विज्ञान विभाग की 16 सेवाएँ इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे मिलेंगी।
- इसके अलावा राज्य परिवहन विभाग, ई-कोर्ट सेवाएँ, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर विभाग, नागर विमानन मंत्रालय की नौ, पैन सेवा पोर्टल की नौ, बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आठ, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा के तहत आठ, भारत निर्वाचन आयोग की सात, यूआईडीएआई की सात, कृषि और किसान कल्याण विभाग की छह, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की छह, उत्तराखंड स्वरोज़गार योजनाएँ की पाँच तथा शहरी विकास निदेशालय की चार सेवाओं का वेब लिंक इस मोबाइल ऐप पर मिलेगा।
- इसी प्रकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उच्च शिक्षा विभाग की तीन-तीन, जीवन प्रमाण की छह, उत्तराखंड जल संस्थान की पाँच, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन, रेल विभाग की तीन, सूचना का अधिकार की तीन, उकाडा उत्तराखंड की तीन, नगर निगम देहरादून की एक और स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन पंजीकरण की एक सेवा का वेब लिंक इस मोबाइल ऐप पर मिलेगा।
- आईटीडीए ने सीएम हेल्पलाइन का भी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिससे प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग भी सीधे मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेज सकेंगे। इसे प्ले स्टोर पर सीएम हेल्पलाइन लिखकर डाउनलोड किया जा सकता है।
- आईटीडीए की तीन सेवाएँ भी शुरू हो गई हैं, जो निम्न हैं-
  - डीएआरसी लेक : यह केंद्रीयकृत डाटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जिसे जीआईएस और ड्रोन का डाटा स्टोर करने के लिये तैयार किया गया है। इस पर स्थानीय ड्रोन पायलटों की सूची भी रहेगी, जो कि कोई भी विभाग एक्सेस कर सकेगा।
  - एसडी-वान : हर तहसील, ब्लॉक, मुख्यालय की ज़िले से कनेक्टिविटी बाधित होने पर भी इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी सुचारु रहेगी। यह हाईस्पीड इंटरनेट प्रणाली है।
  - आईटीडीए-सीएएलसी : इसका पहला सैटेलाइट सेंटर ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। अब प्रदेशभर में यह सेंटर बनेंगे, जिससे युवाओं को ड्रोन चलाने, ठीक करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उत्तराखंड में चालान सहित परिवहन विभाग की छह सेवाएँ हुईं ऑनलाइन

चर्चा में क्यों ?

11 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चालान के प्रशमन शुल्क सहित परिवहन विभाग की छह सेवाएँ ऑनलाइन तथा परिवहन निगम के ही तीन मोबाइल ऐप लॉन्च करके इन सेवाओं का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में परिवहन विभाग की ऑनलाइन हुईं सेवाएँ हैं -
  - **ऑनलाइन टैक्स भुगतान :** स्टेज कैरिज वाहनों के टैक्स पहले कार्यालय में जमा होते थे, लेकिन अब परिवहन वेबसाइट के माध्यम से कहीं से भी ऑनलाइन टैक्स जमा करा सकेंगे।
  - **चालान प्रशमन शुल्क :** अभी तक चालान की फीस दफ्तरों में जमा होती थी, लेकिन अब परिवहन विभाग की ई-चालान वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन जमा करा सकेंगे।
  - **अस्थायी परमिट ऑनलाइन :** परिवहन विभाग के अस्थायी परमिट लेने के लिये अभी तक आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन व शुल्क भुगतान होगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी, अनुमोदन व परमिट डाउनलोड कर सकेंगे।
  - **ऑनलाइन कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट :** संभागीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से अब कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट का आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे और शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। यह परमिट भी ऑनलाइन ही मिलेंगे।
  - **वाहनों के पंजीकरण :** अभी तक निजी वाहनों का पंजीकरण डीलर पॉइंट पर डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ऑनलाइन

नोट :

फीस व टैक्स जमा होता था। इसके बाद डीलर को पूरे कागज़ लेकर आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था। पत्रावलियाँ आरटीओ दफ्तरों में रखनी होती थीं, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दफ्तरों में कागज़ों के ढेर से आज़ादी मिलेगी।

- **ट्रेड सर्टिफिकेट :** व्यवसाय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा।

- परिवहन निगम ने ड्राइवरों के लिये हमसफर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को ड्राइवर के सामने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जाएगा। यह ऐप ड्राइवर की हर हरकत पर नज़र रखेगा तथा नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट करेगा। इसमें सुरक्षित बस संचालन पर रिवार्ड मिलेंगे।
- इसके अलावा अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें जियो फेंसिंग क्षेत्र में आने पर परिवहन निगम के कर्मचारी अपने मोबाइल से ही अपनी हाजिरी लगा सकेंगे।
- इसके अलावा निगम ने फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसके तहत बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर बस की लोकेशन देखने को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी तथा बिना टिकट यात्रा करने वालों को सीसीटीवी की मदद से पकड़ा जा सकेगा। सभी बसों में फ्यूल सेंसर लगाए जाएंगे और केंद्रीय कंट्रोल रूम से सभी बसों की पूरी निगरानी की जा सकेगी।

दिल्ली की तर्ज पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास बनेगी उत्तराखंड की पहली एयरोसिटी

चर्चा में क्यों ?

13 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। ज़मीन की उपलब्धता के साथ ही यह प्रोजेक्ट धरातल पर नज़र आएगा।

प्रमुख बिंदु

- जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास इस परियोजना के लिये ज़मीन तलाशी जा रही है। एयरोसिटी में फाइव स्टार होटल, मॉल, कैफे, रेस्टोरेंट से लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी। इसमें हजारों लोगों के रहने के लिये आवास भी होंगे।
- इस परियोजना के लागू होने पर यह प्रदेश का पहला विश्वस्तरीय अत्याधुनिक शहर होगा।
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके बाद एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी होगी। ऐसे में एयरोसिटी भविष्य का बड़ा बिजनेस हब भी बनकर उभर सकता है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक ले जाने में यह कारगर साबित हो सकती है।
- विदेशों की तर्ज पर यहाँ पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क में जॉगिंग, साइक्लिंग ट्रैक और ध्यान लगाने के लिये हट की व्यवस्था रहेगी। साथ ही लैंड स्केपिंग और आस्ट्रेलियन ग्रास लगाने पर भी विचार चल रहा है। वहीं, हर मौसम में पार्कों में फूल और हरियाली नज़र आएगी।
- मलेशिया के कुआलालंपुर में केएलआईए एयरोपोलिस एयरोसिटी को इस कांसेप्ट का शानदार उदाहरण बताया जाता है। इसी तरह दुबई ने फेस्टिवल सिटी का निर्माण हवाई अड्डे से सिर्फ एक मील की दूरी पर किया है, जिसमें एक लाख लोगों के लिये आवास, स्कूल, मॉल आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी स्थापित की जा चुकी है। यहाँ फाइव स्टार होटल, मॉल, होटल से लेकर कैफे तक की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होने के चलते तेजी से यह बिजनेस हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। इसी प्रकार, मोहाली (पंजाब) में भी एयरोसिटी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

प्रदेश में खुलेंगे 206 पीएम श्री स्कूल

चर्चा में क्यों ?

13 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड में पीएम श्री स्कूल की स्थापना को लेकर बनाए गए नोडल अधिकारी आकाश सारस्वत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से अपने स्तर पर अभी ऐसे 206 स्कूलों का चयन किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य नोडल अधिकारी आकाश सारस्वत के मुताबिक शिक्षा विभाग ने इसके लिये प्रत्येक ब्लॉक और नगर निगम क्षेत्र से सरकारी स्कूलों का चयन भी कर लिया है। राज्य स्तर से चयनित होने के बाद अब केंद्र से इन स्कूलों को मिलने वाले अंकों के आधार पर अंतिम मुहर लगेगी।
- राज्य नोडल अधिकारी आकाश सारस्वत के मुताबिक यह सभी मॉडल स्कूल होंगे, जिन पर आने वाला अधिकतर खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
- राज्य में पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिये शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर को समग्र शिक्षा के उप राज्य परियोजना निदेशक आकाश सारस्वत को नोडल अधिकारी बनाए जाने की घोषणा की है। ज़िला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे।
- राज्य नोडल अधिकारी के मुताबिक प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया जाना है।
- इसके लिये स्कूलों में उपलब्ध खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक से एक सरकारी प्राथमिक स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल को पीएम श्री स्कूल के रूप में राज्य स्तर पर चयनित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र से दो-दो स्कूलों का चयन किया गया है।
- राज्य स्तर पर इन स्कूलों के चयन के बाद इसी सप्ताह इन स्कूलों का केंद्र सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से इन स्कूलों को 'पीएम श्री'स्कूल घोषित किया जाएगा।
- राज्य नोडल अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में 206 स्कूलों के बाद अन्य को भी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों की खास बात यह होगी कि इनमें छात्र-छात्राओं को हर संभव सुविधाएँ मिलेंगी।

लक्ष्य सेन को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। खेल-कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये देश भर से 25 खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जिनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कार विजेता 30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
- 16 अगस्त, 2001 को अल्मोड़ा में जन्मे शटलर लक्ष्य सेन मूलरूप से ज़िले के सोमेश्वर के ग्राम रस्यारा निवासी हैं। इनके दादा जी सीएल सेन ने सिविल सर्विसेस में राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं कई खिताब अपने नाम किये, जबकि पिता डीके सेन भी वर्तमान में कोच हैं। पहले वह साई के कोच थे।
- लक्ष्य ने ज़िला, राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम किये। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पैठ जमाई। 10 वर्ष की उम्र में लक्ष्य ने इज़राइल में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब स्वर्ण पदक के रूप में जीता था।
- लक्ष्य ने 8 अगस्त, 2022 को बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के एंग जे योंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हराया था। लक्ष्य पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और वर्ष 2022 में जनवरी में इंडिया ओपन में सुपर 500 का खिताब जीत चुके हैं।
- लक्ष्य ने लिनिंग सिंगापुर यूथ इंटरनेशनल सीरीज़ में स्वर्ण, इज़राइल जूनियर इंटरनेशनल के डबल और सिंगल में स्वर्ण, इंडिया इंटरनेशनल सीरीज़ के सीनियर वर्ग में स्वर्ण, योनेक्स जर्मन जूनियर इंटरनेशनल में रजत, डच जूनियर में कांस्य, यूरेशिया बुल्गारियन ओपन में स्वर्ण, ऐशिया जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण, यूथ ओलंपिक में रजत, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया है।

नोट :

- उल्लेखनीय है की खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिये हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिये जाते हैं। पिछले चार वर्षों की अवधि में 'खेल-कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसी खूबियाँ दिखाने के लिये अर्जुन पुरस्कार' दिया जाता है।

70वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले (गौचर मेला) का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 70वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले (गौचर मेला) का शुभारंभ किया और मेले के संस्थापक पत्रकार स्व. गोविंद प्रसाद नौटियाल की मूर्ति का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश गैरोला 'पहाड़ी'को गोविंद प्रसाद नौटियाल स्मृति पत्रकार सम्मान से नवाजा। इस मौके पर सीएम ने देवेश जोशी की ओर से 'कै. धूमसिंह चौहान'पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया।
- उल्लेखनीय है कि गौचर मेला लगभग 75 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। पहले यह मेला व्यापार के लिये प्रसिद्ध था, मगर समय के साथ मेले का रूप बदला और अब ये सांस्कृतिक मेले के रूप में मनाया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गढ़-कुमाऊँ की संस्कृति दिखती है।
- गौचर मेला अब तक 11 बार अलग-अलग कारणों से नहीं हो पाया। गौचर मेला वर्ष 1943 के नवंबर माह में भोटिया व्यापारिक मेले के नाम से शुरू हुआ था, जो 1953 तक इसी नाम से चलता रहा।
- यह मेला उस समय पूर्णतया एक व्यापारिक मेला था। मेले में मुख्यतया तिब्बती ऊन, तिब्बती पश्मीना ऊन, च्यालकू, बकरियाँ, तिब्बती कालीन, दन, हींग, तिब्बती नमक, कस्तूरा एवं भोटिया चाय का व्यापार होता था, लेकिन 1962 में युद्ध के बाद चीन के साथ आए रिश्तों में तनाव के कारण अचानक तिब्बत के व्यापारिक मार्ग बंद हो गए थे।
- वर्ष 1947 से मेले का आयोजन नवंबर में शुभ तिथि निकालकर किया जाता था। तिब्बत से व्यापार बंद होने के बाद यह मेला औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले के रूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर होने लगा। इस मेले को एक बार ज़िला परिषद चमोली और दो बार टाउन एरिया कमेटी गौचर की ओर से संचालित किया जा चुका है।

प्रसिद्ध जौलजीबी मेला का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली एवं गोरी नदी के संगम स्थल जौलजीबी में भारत और नेपाल सीमा पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जौलजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी-2022 का शुभारंभ किया। यह मेला 24 नवंबर तक लगेगा।

प्रमुख बिंदु

- सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेला भारत, नेपाल तथा तिब्बत के पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देता रहा है। यह मेला भारत और नेपाल के बीच संस्कृति, सभ्यता, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर देश के रिश्तों को ऑक्सीजन देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले के शुभारंभ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित धारचूला के एलधारा भूस्खलन क्षेत्र का उपचार उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत की तर्ज़ पर किया जाएगा। क्षेत्र की काली नदी सहित सीमा पर अन्य स्थानों के भूस्खलन स्थलों के लिये बृहद् योजना की जा रही है। प्रस्ताव रक्षा और गृह मंत्रालय को भेजे गए हैं।
- उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिये काली नदी पर डबल लेन मोटर पुल का निर्माण किय जा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण और चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाने से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री इसी मार्ग से होकर जाएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

नोट :

प्राकृतिक खेती के लिये प्रति हेक्टेयर पाँच हज़ार रुपए देगी केंद्र सरकार

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के कृषि निदेशक गौरीशंकर ने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार प्रति हेक्टेयर पाँच हज़ार रुपए प्रतिवर्ष किसानों को देगी। इस धनराशि से किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कृषि निदेशक गौरीशंकर ने बताया कि योजना के तहत पहले साल किसानों को खेती करने के तरीके और खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिये 11 ज़िलों में 128 क्लस्टर का चयन भी किया गया है।
- उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग व ऊधमसिंह नगर ज़िले को फिलहाल प्राकृतिक खेती योजना में शामिल नहीं किया गया है। अन्य 11 ज़िलों में प्राकृतिक खेती पर काम किया जाएगा। चयनित क्लस्टरों में किसी तरह की रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिये प्राकृतिक खेती पर ज़ोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती के लिये लगभग 6400 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल चयनित किया गया है, जिसमें 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिये 'मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना'शुरू की है। इस योजना के माध्यम से भी किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही गैप फंडिंग की जाएगी।

उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप होगा अपग्रेड

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग (यूएसडीएमए) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की की ओर से तैयार किये गए मोबाइल एप्लीकेशन 'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट'ऐप को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिये यूएसडीएमए की ओर से 58 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य है, जिसने प्रारंभिक भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित की है।
- विश्व बैंक परियोजना के वरिष्ठ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गिरीश जोशी ने बताया कि भूकंप अलर्ट ऐप सेंसर आधारित प्रणाली पर काम करता है। अभी तक राज्य में चकराता से लेकर पिथौरागढ़ तक करीब 163 सेंसर लगे हैं, जिनसे प्राप्त होने वाले इनपुट के आधार पर 'अलर्ट ऐप'भूकंप आने की स्थिति में बीप बजाता है, लेकिन सटीक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिये सेंसर बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को अपग्रेड करने के लिये राज्य के विभिन्न हिस्सों में 350 नए स्थानों पर सेंसर लगाए जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राज्य में 500 से अधिक सेंसर स्थापित करके मौजूदा नेटवर्क को और अधिक सघन बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यूनतम 5-10 किमी. की दूरी पर कम-से-कम एक सेंसर लगाना है। इन सेंसरों का फायदा केवल उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली सहित आसपास के राज्यों को भी होगा।
- भूकंप विशेषज्ञ गिरीश जोशी ने बताया कि जब भूकंप आता है तो पी तरंगें और एस तरंगें केंद्र से अलग-अलग दिशाओं में ऊपरी सतह (ग्राउंड लैंडस्केप) की ओर सफर करती हैं। पी तरंग तेज़ी से यात्रा करती हैं और लैंडस्केप में लगे सेंसर को ट्रिगर करती हैं। सेंसर से डाटा कंट्रोल रूम पहुँचता है और तुरंत एक अलर्ट जारी किया जाता है। इस तरह से उपयोगकर्त्ता को मोबाइल ऐप के माध्यम से अलर्ट मिल जाता है।
- यूएसडीएमए का दावा है कि 12 नवंबर को नेपाल में आए 5.4 मैग्नीट्यूट के भूकंप का उत्तराखंड सहित दिल्ली में कुछ मोबाइलों पर अलर्ट प्राप्त हुआ था। अलर्ट उन्हीं मोबाइल पर प्राप्त हुआ था, जिन्होंने ऐप को समय-समय पर अपडेट किया था।

नोट :

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 पर कैबिनेट की मुहर

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 पर मुहर लग गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में 26 प्रस्ताव आए, जिनमें से 25 पर मुहर लग गई। इनमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण का कानून सख्त बना दिया गया है।
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के तहत अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को दस साल तक की सजा होगी।
- उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करने पर एक से पाँच साल की सजा और 25 हज़ार रुपए जुर्माना है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा करने पर दो से सात साल की सजा होगी और 25 हज़ार जुर्माना होगा।
- प्रदेश में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब तीन से दस साल तक की सजा होगी, पहले अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से पाँच लाख रुपए की प्रतिपूर्ति भी मिल सकेगी।
- मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले यह असंज्ञेय अपराध था। अब सरकार इसे विधानसभा पटल पर रखेगी।

बर्ड वॉचिंग ट्रैल के रूप में विकसित होगा एबट माउंट क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को चंपावत ज़िला के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि ज़िले के एबट माउंट क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के लिये क्षेत्र को बर्ड वॉचिंग ट्रैल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास विभाग की ओर से इसके लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर मंज़ूरी के लिये शासन को भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- अरविंद गौड़ ने बताया कि बर्ड वॉचिंग ट्रैल के लिये पूर्व में पर्यटन सचिव की ओर से निर्देश जारी किये जाने के बाद विभाग ने कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम के माध्यम से डीपीआर शासन को भेजी है जिसे जल्द मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है।
- एबट माउंट में प्रस्तावित बर्ड वॉचिंग ट्रैल के लिये पर्यटन विभाग की भूमि का सीमांकन करने के साथ ही सुरक्षा के लिये चहारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से चहारदीवारी के निर्माण का प्रस्ताव भी राजस्व विभाग के माध्यम से शासन को भेजा है।
- एबट माउंट में पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्यटन विभाग की ओर से आठ ईको हट्स का निर्माण किया गया है। वहीं अब एबट माउंट में पर्यटकों के लिये हेलिपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा।
- एबटमाउंट में प्रस्तावित हेलिपोर्ट के जरिये बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा वहीं हेलिपोर्ट का प्रयोग आपदा के समय में राहत और बचाव कार्य के लिये भी किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के ऐसे गाँव, जो भारत के प्रथम गाँव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिये 'मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना' शुरू की जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमाओं पर स्थित गाँवों को अंतिम गाँव की बजाय प्रथम गाँव कहा था। ये गाँव देश के प्रथम गाँव के साथ प्रहरी भी हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य की पहली प्राथमिकता है कि देश के इन प्रथम गाँवों का सुनियोजित विकास होना चाहिये। गाँवों में स्वच्छता के लिये 'मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र'योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गाँव में एक पर्यावरण मित्र (स्वच्छक) की तैनाती की जाएगी तथा ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिये 'मुख्यमंत्री चौपाल'शुरू की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इन गाँवों में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिवस वहाँ के लिये विशेष महत्त्व के होते हैं तथा गाँवों में इन विशेष दिवसों को चिह्नित कर उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ। ग्राम सभा का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इनमें उन गाँवों के बाहर रहने वाले प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिये विशेष रूप से प्रेरित किया जाए।
- उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो, इसके लिये चौपाल लगाई जाए। इसके लिये ग्राम सभावार रोस्टर भी बनाया जाए। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन चौपालों में दिये जाने वाले सुझावों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए गाँवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए।
- उन्होंने बताया कि असली भारत गाँवों में बसता है। राज्य के समग्र विकास के लिये गाँवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये तथा गाँवों के विकास के लिये किसी गाँव में एक कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाए, जिसमें गाँवों के विकास से संबंधित प्रस्ताव हों।

उत्तराखंड में बनाई जाएगी पोल्ट्री वैली

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के पशुपालन एवं दुग्ध विकास सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने देहरादून में हुई परियोजना निदेशकों की बैठक में बताया कि पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार गोट वैली के बाद राज्य में पोल्ट्री वैली योजना शुरू करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य में एक साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चकराता में पोल्ट्री वैली बनाई गई थी, जिसमें सफलता मिलने पर अब अन्य ज़िलों में पोल्ट्री वैली बनाई जाएगी।
- उन्होंने कहा कि दुग्ध विकास विभाग के माध्यम से राज्य के सभी ज़िलों में आंचल कैफे खोले जाएंगे। जहाँ पर दूध व अन्य उत्पाद एक ही जगह मिल सकेंगे। आंचल कैफे और पोल्ट्री वैली की शुरुआत 25 नवंबर को की जाएगी। इसके लिये अधिकारियों को तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिये गए।
- उन्होंने बताया कि आंचल कैफे के लिये 41 स्थानों का चयन किया गया है। आंचल कैफे में दूध के अलावा शेक, आइसक्रीम, पिज्जा, दूध से बने उत्पाद मिलेंगे। कैफे से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेंगे। साथ ही, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
- परियोजना निदेशक डेयरी जयदीप अरोड़ा ने बताया कि देहरादून के घंटाघर में एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में आंचल कैफे तैयार कर दिया गया है।

उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 का ड्राफ्ट जारी

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति-2022 का ड्राफ्ट जारी करते हुए इस पर सुझाव मांगे हैं।

प्रमुख बिंदु

- आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक की क्षमता है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिये 600 मेगावाट, आवासीय प्रोजेक्ट के लिये 250 मेगावाट, कमर्शियल व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिये 750 मेगावाट, इंस्टीट्यूशंस के लिये 350 मेगावाट और एग्रीकल्चर के लिये 50 मेगावाट की क्षमता आँकी गई है।

नोट :

- उत्तराखंड सोलर पॉलिसी-2022 में यह प्रावधान किया गया है कि यूपीसीएल सौर ऊर्जा का एक ग्रीन टैरिफ प्रस्ताव तैयार करेगा, जो कि नियामक आयोग को भेजा जाएगा। नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिये ग्रीन टैरिफ चुनने का विकल्प दे सकता है। इसके अलावा पीक आवर्स में ग्रिड में सौर ऊर्जा देने वालों को फीड इन टैरिफ से प्रोत्साहित कर सकता है। आसान पहुँच व निगरानी के लिये वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) और ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- नई पॉलिसी में उरेडा की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ाई गई हैं। इसके तहत उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सिंगल विंडो के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। इसके आवेदन के लिये 10 हज़ार रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से शुल्क देय होगा।
- उरेडा को लैंडबैंक भी बनाना होगा। सभी सरकारी ज़मीनें और भवनों की सूची बनानी होगी, जहाँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसी प्रकार, ऐसी निजी भूमि भी चिह्नित करनी होंगी, जिन पर कोई प्राइवेट व्यक्ति लीज़ पर अपना प्रोजेक्ट लगा सके।
- ज़मीन की लीज़ डीड या ज़मीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। निजी कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाने पर लैंड यूज़ बदलने की फीस पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन या लीज़ के कागज़ों में कोर्ट फीस पूरी तरह से माफ होगी। सौर ऊर्जा वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकारी भूमि पर लगाने वाले व्यक्तियों को लीज मूल्य में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोज़गार की भी गारंटी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज़ पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
- 25 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट के आवंटन के लिये ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्क्रीनिंग एंड इंपावर्ड कमेटी (एसएलएससी) बनेगी। प्रोजेक्ट के एप्रूवल से अलग आने वाली परेशानियों को दूर करने, पॉलिसी में किसी तरह का संशोधन करने के लिये स्टेट लेवल एनर्जी कमेटी (एसएलईसी) का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा। इसमें ऊर्जा सचिव सहित आठ सदस्य होंगे। भूमि संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिये उत्तराखंड सोलर पावर लैंड अलॉटमेंट कमेटी (यूएसपीएलएसी) का गठन भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा। इसमें ऊर्जा सचिव सहित चार सदस्य होंगे।

सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव-2022 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

19 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट) देहरादून एवं ज़िला प्रशासन चंपावत के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव-2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर महोत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु 5 वैज्ञानिकों व व्यक्तियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि यह महोत्सव ऐसा पहला विज्ञान आधारित महोत्सव है जो दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के लिये आयोजित किया जा रहा है। इसमें राज्य के सीमांत 6 जनपदों से आए सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों के अलावा वैज्ञानिक और प्रबुद्ध जन शामिल हुए।
- उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य विषय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, विकास के दो ऐसे घटक हैं जो विज्ञान आधारित विकास के लिये सुदृढ़ नींव का काम करते हैं। यह प्रथम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव राज्य में वैज्ञानिक अवधारणा को पुष्ट करने का कार्य करेगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस विज्ञान महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक दूरस्थ क्षेत्र तक वैज्ञानिक तकनीक पहुँचाना और जन-जन तक विज्ञान और हर बच्चे में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है।
- महोत्सव में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं (पोस्टर मेकिंग, ड्रामा, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ आदि) के माध्यम से सभी बच्चे अपनी अभिरुचियों से रूबरू होंगे।
- उन्होंने बताया कि चंपावत की भौगोलिक परिस्थितियाँ पूरे उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ पर मैदानी, उच्च एवं मध्य हिमालयी

नोट :

क्षेत्र हैं, इसीलिये सरकार ने आदर्श उत्तराखंड के लिये सबसे पहले चंपावत जनपद को मॉडल जनपद के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिये राज्य सरकार के सभी विभाग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और यूकॉस्ट इसमें नोडल एजेंसी का कार्य कर रहा है।

- राज्य में वैज्ञानिक सोच को जागृत करने, विज्ञान शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु और नवाचार अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिये साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के हर क्षेत्र तक अनुसंधान और शोध गतिविधियों को पहुँचाने हेतु लैब्स ऑन व्हील का कांसेप्ट राज्य के हर जनपद के लिये लाया गया है, ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक भी शोध और अनुसंधान गतिविधियाँ पहुँच सकें।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जागरूकता हेतु हल्द्वानी में यूकॉस्ट और एरीज साथ मिलकर 'एस्ट्रो पार्क'का निर्माण कर रहे हैं जो पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान का मिश्रण होगा।
- अल्मोड़ा में एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर विज्ञान आधारित गतिविधियाँ और कार्यक्रम संचालित होंगे तथा चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है ताकि क्षेत्र में विज्ञान आधारित शिक्षा और जागरूकता का संचार हो।

देहरादून नगर निगम ने लॉन्च किया 'बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप'

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने देहरादून नगर निगम में सभी बल्क वेस्ट जनरेट-आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट, होटल एवं रेस्टोरेंट परिसर से ही कचरे को अलग-अलग करने के लिये 'बल्क वेस्ट जनरेट ऐप'लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि देहरादून में बड़ी संख्या में फ्लैट, अपार्टमेंट, होटल, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ से बल्क में काफी कूड़ा पैदा होता है, लेकिन सभी कूड़ा बिना अलग-अलग किये ही सीधे निगम की गाड़ियों में डाल देते हैं, जबकि नियमानुसार ऐसे संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंटों को कूड़ा अलग-अलग देना होता है।
- 'बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप'के अंतर्गत देहरादून नगर निगम में जितने भी बल्क जनरेट हैं, उन्हें इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर किसी ने कूड़ा अलग-अलग करके नहीं दिया तो निगम उसका कूड़ा नहीं उठाएगा और उस अपार्टमेंट, होटल, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करेगा।
- इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद निगम के पास ऐसे सभी संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंटों का डाटा तो होगा ही, इसके साथ ही यह भी पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ से कूड़ा उठेगा। ऐप में बाकायदा अपार्टमेंट, होटल, रेस्टोरेंटों का नंबर होगा। इसके लिये उन्हें एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। कूड़ा एकत्रित होने पर संबंधित संस्थान फोन करेंगे और इसके बाद गाड़ी मौके पर पहुंचकर कूड़ा उठाएगी। बिना क्यूआर कोड स्कैन किये कूड़ा नहीं उठाया जाएगा।

सहस्त्रधारा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीड्रोम

चर्चा में क्यों?

24 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड नागरिक उडन्यन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि देहरादून सहस्त्रधारा में अगले यात्रा सीजन तक आधुनिक सुविधाओं से हेलीड्रोम का निर्माण किया किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि केदारनाथ धाम के लिये सिरसी, गुप्तकाशी, फाटा से संचालित होने वाली हेली सेवा में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए अगले साल से सहस्त्रधारा से केदारनाथ, बदरीनाथ के लिये हेली सेवा संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- उत्तराखंड नागरिक उडन्यन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। हेली सेवा संचालन के लिये यूकाडा की ओर से एविएशन कंपनी को ऑफर दिया जाएगा तथा डीजीसीए की अनुमति मिलने के बाद देहरादून से भी यात्रियों को सीधे हेली सेवा का लाभ मिलेगा।

नोट :

- यहाँ पर यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएँ मिलेंगी। इस हेलीड्रोम की क्षमता 500 यात्रियों की होगी। इससे हेलिकॉप्टर की पार्किंग के अलावा यात्रियों को एयरपोर्ट पर कई तरह की सुविधाएँ मिलेंगी।
- यूकाडा की ओर से सहस्त्रधारा हेलीपैड विस्तार के लिये नगर निगम की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिये नगर निगम को भूमि के बदले 13 करोड़ रुपए भुगतान किया जाएगा।

उत्तराखंड और अमेरिकी कंपनी के बीच हुआ दो साल का करार

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड की नियोजन सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य सरकार ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता अमेरिकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार का जिम्मा देते हुए कंपनी के साथ दो साल का करार किया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य सरकार का मैकेंजी ग्लोबल के साथ करार होने से राज्य अगले पाँच साल में आर्थिक विकास दर (जीडीपी) दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। वर्तमान में राज्य में 05 प्रतिशत जीडीपी का अनुमान है।
- छह महीने में कंपनी विकास की संभावनाओं वाले उन क्षेत्रों का चयन करेगी, जिनमें वह देश और दुनिया के नामी विशेषज्ञ कंपनियों से निवेश करा सकती है। डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, मैकेंजी ग्लोबल कंपनी किसी राज्य में पहली बार काम करेगी।
- इस करार के तहत कंपनी छह महीने राज्य में उन सेक्टरों का चयन करेगी, जिनमें नए निवेश और सुधारों के जरिये तरक्की की जा सकती है। बाकी के डेढ़ साल में चिह्नित क्षेत्रों में निवेश के लिये नामी कंपनियों को लाएगी।
- एजेंसी फसलों और उत्पादों की पैदावार में वृद्धि और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिये निवेश कराएगी। उत्पादों को निर्यात बाज़ार दिलाने का भी काम करेगी। यदि कंपनी बेहतर परिणाम देगी, तो उसके करार को आगे बढ़ाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मैकेंजी ग्लोबल को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है। वियतनाम में कंपनी ने चुनिंदा उत्पादों चावल, कॉफी, केला, मशरूम पर काम किया है। उनकी गुणवत्ता सुधारी, पैदावार बढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराया। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये, न्यू टाउनशिप, पर्यटन, उद्यान, ऊर्जा, आयुष, योग, वेलनेस टूरिज्म, आईटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री समेत कई अन्य क्षेत्रों में कंपनी काम कर सकती है।

उत्तराखंड में ड्रोन ट्रैफिक सँभालने के लिये बनेंगे कॉरिडोर

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास एजेंसी (आईटीडीए) के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि ड्रोन तकनीक में नए प्रयोगों के साथ प्रदेश में ड्रोन ट्रैफिक सँभालने के लिये सभी ज़िलों में कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हवाई सेवाओं की तर्ज पर ये ऐसे रास्ते होंगे, जिनसे सरकारी और निजी ड्रोन उड़ान भर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि ड्रोन के भविष्य में उपयोग को देखते हुए इसके लिये रास्ते तैयार करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने ड्रोन कॉरिडोर बनाने काम शुरू किया है।
- आईटीडीए के निदेशक ने बताया कि प्रदेश के सभी ज़िलों में ड्रोन संचालन के लिये जो कॉरिडोर बनेंगे, उन्हें आपस में लिंक किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समर्पित रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नियम को तोड़ने वालों पर भविष्य में कार्रवाई भी हो सकेगी।
- उन्होंने बताया कि ड्रोन कॉरिडोर बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार किये जाएंगे, जो हवाई सेवाओं को बाधित न करें। इसके अलावा सीमांत प्रदेश होने के नाते तमाम प्रतिबंधित क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश में उत्तरकाशी से दून या अन्य जगहों पर ड्रोन संचालन का कोई समर्पित कॉरिडोर नहीं है, जिससे कई ड्रोन

नोट :

को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे अधिक समय लगने और ड्रोन की बैटरी भी जल्द खत्म होने का खतरा है। ड्रोन कॉरिडोर के बन जाने से उड़ान का समय तो कम होगा ही, उसकी बैटरी भी लंबी दूरी की उड़ान में मदद करेगी।

- ड्रोन के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे विकास के मद्देनज़र उत्तराखंड सरकार जल्द ही ड्रोन नीति लाने जा रही है। आईटीडीए ने इसका ड्राफ्ट शासन को भेजा है। इसके तहत ड्रोन संचालन से लेकर ड्रोन की खरीद तक के सभी प्रावधान किये जाएंगे। जल्द ही यह नीति कैबिनेट में आने का अनुमान है।

गौचर व चिन्यालीसौड़ के लिये जल्द हवाई सेवा, पिथौरागढ़ से शुरू होंगी फिक्स्ड विंग एयरक्रॉफ्ट सेवाएँ

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर गौचर व चिन्यालीसौड़ के लिये हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई।

प्रमुख बिंदु

- 'उड़ान योजना' के तहत जल्द ही गौचर और चिन्यालीसौड़ के लिये हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसमें 20 सीट फिक्स्ड विंग एयरक्रॉफ्ट का संचालन किया जाएगा। योजना के अगले टेंडर में दोनों स्थानों की हवाई सेवा को शामिल किया जाएगा।
- इसके अलावा पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्रॉफ्ट सेवाएँ शुरू करने के लिये स्पाइसजेट व बिग चार्टर्ड एयरलाइन को कार्य के आदेश जारी किये गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ में पवनहंस को निर्बाध और समयबद्ध तरीके से सेवाएँ संचालित करने के लिये निर्देशित करने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप विकसित करने के लिये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सर्वे रिपोर्ट दिसंबर में ही देनी है।
- मुख्यमंत्री ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानकों के अनुरूप विस्तार देने के लिये भूमि का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से शीघ्र भौतिक सर्वे करने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सीएम को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में हवाई सेवा से संबंधित सभी प्रस्तावों को जल्द क्रियान्वित किया जाएगा।

नोट :